



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933

No. 158]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

विषय : चीन जन.गण., इंडोनेशिया, थाइलैंड और यूएई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/45/2010-डीजीएडी.—यतः मै. सेंट-गोबेन गायप्रॉक इंडिया लि. (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा जाएगा) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटिवस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने चीन, इंडोनेशिया, थाइलैंड और यूएई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु चीन, इंडोनेशिया, थाइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने का अनुरोध किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को “क्षति” तथा कथित पाटन एवं “क्षति” के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतदद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

3. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की मोटाई और लम्बाई-चौड़ाई वाले प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

(i) 5% तक की जल अवशोषण क्षमता वाले जिप्सम बोर्ड। ये बोर्ड सामान्यतः “आर्दता रोधी बोर्ड” कहलाते हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से वहाँ किया जाता है जहाँ आर्दता प्रतिरोधन अपेक्षित होता है। चुनिंदा जल-प्रतिवारण योजकों के इस्तेमाल से यह आर्दता प्रतिरोधन क्षमता प्राप्त की जाती है।

(ii) बोर्ड की प्रति मिलीमीटर मोटाई में अनुप्रस्थ दिशा में 24 न्यूटन और अनुदैर्घ्य दिशा में 50 न्यूटन के न्यूनतम ब्रेकिंग लोड वाले जिप्सम बोर्ड। विशिष्ट अनुप्रयोजन के लिए डिजाइन किए गए बोर्ड “आधात प्रतिरोधी बोर्ड” अथवा “अग्नि प्रतिरोधी बोर्ड” कहलाते हैं।

4. आम व्यापारिक शब्दावली में प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड को स्टेंडर्ड जिप्सम बोर्ड, रेग्युलर जिप्सम बोर्ड या जिप्सम बोर्ड भी कहा जाता है। संबद्ध वस्तु का प्रयोग सर्पेंड सीलिंग या पार्टिशन हेतु आंतरिक विनिर्माण में किया जाता है। संबद्ध वस्तु अध्याय शीर्ष 68091100 के अंतर्गत वर्गीकृत है हालांकि इसका आयात 68099900, 68091900 आदि जैसे टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत किए जाने की सूचना मिली है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग तथा उसका मत

5. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. सेंट-गोबेन गायप्रॉक इंडिया लि. द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के अनुसार आवेदक द्वारा किया जाने वाला उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है जो कुल भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है। सेंट-गोबेन गायप्रॉक इंडिया लि. के अलावा मै. लाफार्ज बोरल जिप्सम इंडिया प्रा. लि. (एलबीजीआई) भी कथित रूप से संबद्ध वस्तु का उत्पादक है; तथापि आवेदक के अनुसार मै. लाफार्ज बोरल जिप्सम इंडिया प्रा. लि. ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इस कारण वह नियमानुसार घरेलू उद्योग का दर्जा पाने का पात्र नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनी का प्रमुख हिस्सा है। अतः प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमवाली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदण्डों को पूरा करता है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु, जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, प्रकार्यों अथवा अंतिम प्रयोग में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के तहत उन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा संयुक्त अरब अमीरात हैं।

सामान्य मूल्य

चीन के लिए सामान्य मूल्य :

8. नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 8 के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि चीन जन गण में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं। गैर बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उपर्युक्त पूर्वानुमान तथा उत्तर देने वाले निर्यातकों की ओर से उसका खण्डन किए जाने के अध्यधीन नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के संदर्भ में चीन जन गण में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का पूर्वानुमान लगाया गया है। आवेदक ने एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में थाईलैंड पर विचार किए जाने का प्रस्ताव किया है जो वर्तमान जांच में भी एक संबद्ध देश है। उन्होंने कहा है कि संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने की चीन की क्षमता, थाईलैंड की विनिर्माण क्षमता के लगभग बराबर ही है। उनकी औद्योगिक संरचना, संयंत्रों की औसत क्षमता, लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी काफी हद तक और पर्याप्त रूप से चीन से मिलती-जुलती है। थाईलैंड एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है जहाँ स्थानीय उत्पादकों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने के साथ-साथ आयातित उत्पाद भी प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं। इस तरह की परिस्थितियां बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों का अच्छा संकेतक होती हैं। अतः यह कहा गया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित संगत सूचना जांच के दौरान, थाईलैंड से प्राप्त की जा सकती है।

इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा यू.ए.ई के लिए सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने यह वक्तव्य देते हुए कि वे इन देशों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमतों के संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं और न ही ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इंडोनेशिया, थाईलैंड और यू.ए.ई के संबंध में सामान्य मूल्यों का परिकलन किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्ययों तथा समुचित लाभ सहित उपलब्ध कराए गए उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर इन देशों के संबंध में वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

10. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसूचना सेवा (आई बी आई एस) से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का अनुमान लगाया गया है। निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री

बीमा, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, पत्तन प्रहस्तन तथा पत्तन प्रभारों इत्यादि में कीमत समायोजन करने की अनुमति दी गई है। पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमतों से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जिससे संबद्ध देशों के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस तथ्य के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। अनुमान है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदक ने इस बात से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कथित पाटन के परिणामस्वरूप, पाटित आयातों की वृद्धिकारी मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूँजी पर आय, नकद प्रवाह, उत्पादन, क्षमता उपयोग में गिरावट के रूप में ‘क्षति’ हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई ‘क्षति’ के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2007 - मार्च, 2008, अप्रैल 2008 - मार्च 2009, अप्रैल 2009 - मार्च 2010 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों/आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में उत्पाद से संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित पद्धति एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा में जांच से संगत सूचना लिखित में निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं0 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110001

समय-सीमा

15. इस जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40(चालीस) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि जिन नियातिकों एवं आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उनसे अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जा सकता है कि निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अगोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराना

16. नियम के नियम 6(7) के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

17. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास एक सार्वजनिक फाइल होती है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

असहयोग

18. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2011

Sub. : Initiation of Anti-Dumping Duty Investigation concerning imports of Plain Gypsum Plaster Boards originating in or exported from China PR, Indonesia, Thailand and UAE

1. **No. 14/45/2010-DGAD** - Whereas M/s Saint-Gobain Gyproc India Ltd (hereinafter referred to as applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) alleging dumping of Plain Gypsum Plaster Boards (herein after referred to as subject goods) originating in or exported from China, Indonesia, Thailand, and UAE for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Plain Gypsum Plaster Board (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China, Indonesia, Thailand, and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred to as the subject countries) for initiation of anti dumping investigation for levy of anti dumping duties on the subject goods.
2. And whereas, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is Plain Gypsum Plaster Boards of **all thicknesses** and dimensions but excluding the following:

(i) Gypsum Boards having water absorption up to and including 5%. These Boards are generally referred to as "Moisture Resistant Boards" which have specific application in places where moisture resistance is desired. These moisture resistant properties are acquired by addition of certain water-repelling additives.

(ii) Gypsum Boards having a minimum breaking load of 24 Newtons in the transverse direction and 50 Newtons in the longitudinal direction per millimeter of thickness of the Board. Boards that are typically designed for special application are characterized as "Impact Resistant Boards" or "Fire Resistant Boards"

4. The Plain Gypsum Plaster Boards are also referred to as Standard Gypsum Boards, Regular Gypsum Boards or Gypsum Boards in common trade parlance. The subject goods are used in interior construction in suspended ceiling and partition applications. The subject goods are classified under chapter heading 68091100, although reportedly being imported under tariff headings such as 68099900, 68091900 etc. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

5. The application has been filed by M/s Saint-Gobain Gyproc India Ltd on behalf of the domestic industry. As per the evidence available on record, the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods constituting more than 50% of Indian production. Apart from Saint-Gobain Gyproc India Ltd, M/s Lafarge Boral Gypsum India Pvt. Ltd. (LBGI) is reportedly a producer of the subject goods as well. However, as stated by the applicant, M/s Lafarge Boral Gypsum India Pvt. Ltd. (LBGI) has imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation (POI), thereby making them ineligible for the status of the domestic industry as per the Rules. On the basis of information available the Authority notes that the applicant company constitutes a major proportion in Indian production. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

LIKE ARTICLE

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

COUNTRIES INVOLVED

7. The countries involved in the present investigation are China, Indonesia, Thailand and United Arab Emirates.

2733 GI/11-3

NORMAL VALUE

Normal value for China:

8. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. The applicant has proposed that Thailand be taken as an appropriate market economy third country which is also a subject country in the current investigation. They stated that the capacity in China for manufacturing the subject goods is close to the manufacturing facility in Thailand. The industry structure, the average capacity of plants, the cost structure, the production process and the technology are reasonably and fairly close to that found in China. Thailand is a market economy country with considerable competition within the local producers as well as from imported goods. Such conditions are a good indicator of market determined prices. It is stated that the relevant information regarding the determination of normal value, therefore, can be obtained from Thailand during the course of the investigation.

Normal Value for Indonesia, Thailand and UAE

9. The applicant has constructed the normal values in respect of Indonesia, Thailand and UAE stating that neither they were able to get any documentary evidence or reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in these countries nor the same are available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in respect of these countries on the basis of best estimates of cost of production, including selling, general, administrative & finance expenses and reasonable profit as made available by the applicant for the purpose of this initiation.

EXPORT PRICE

10. Export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by considering transaction-wise import data as provided by the applicant from International Business Information Services. Price adjustments have been allowed on account of Ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and port charges etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

DUMPING MARGIN

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by exporters

from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

INJURY AND CAUSAL LINK

12. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and decline in profitability, return on capital employed, cash flow, market share, production, capacity utilization etc. of the domestic industry. There is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

PERIOD OF INVESTIGATION

13. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January 2010 to 31st December 2010 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods April 2007-March 2008, April 2008-March 2009, April 2009-March 2010 and the POI.

SUBMISSION OF INFORMATION

14. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies/Economic and Cultural Centre in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110011.

TIME LIMIT

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record it's findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules .It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

16. In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reasons thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

17. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

NON-COOPERATION

18. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority